

UPSC CSE 2019 MAINS PAPER 6 SEPTEMBER 29, 2019 LAW OPTIONAL PAPER - I QUESTION PAPER

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : तीन घंटे
Time Allowed : **Three Hours**

अधिकतम अंक : 250
Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हुए हैं ।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each section.

The number of marks carried by a question /part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) महत्वपूर्ण ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से, केन्द्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित 'सार और तत्त्व' (पिथ और सब्सटैंस) के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए ।

Discuss the doctrine of 'Pith and Substance' relating to the distribution of legislative powers between the Centre and the States with the help of the landmark judicial decisions.

10

- (b) “ 'लोकपाल' के पद का उद्देश्य न्याय-निर्णयन करना नहीं है, अपितु प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों के अन्वेषण के लिए एक अलग और अनौपचारिक नियमित व्यवस्था (तंत्र) प्रदान करना है ।” भारत में 'लोकपाल' के पद के औचित्य के प्रतिपादन के साथ, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

“The purpose of the office of the 'Lokpal' is not to adjudicate, but to provide regular machinery for investigating grievances against the administration in a discrete and informal manner.” Critically examine this statement by providing proper justification of the office of the 'Lokpal' in India.

10

- (c) “नैसर्गिक न्याय को शीघ्रता और निष्पक्षता के साथ देने के लिए 'औडि औल्टरम पार्टम' (दूसरे पक्ष को सुनो) नियम अत्यंत नम्य, लचीली और अनुकूलनशील संकल्पना है ।” निर्णयज वाद-विधि की सहायता से कथन का परीक्षण कीजिए ।

“ 'Audi alteram partem', rule is a very flexible, malleable and adaptable concept of natural justice to adjust the need for speed and obligation to act fairly.” Examine the statement with the help of decided case-law.

10

- (d) “संसदीय-विशेषाधिकारों का मुद्दा संसद और न्यायपालिका के मध्य विवाद और झगड़े की जड़ बना रहा है ।” विनिर्णीत वादों की पृष्ठभूमि में इस कथन का विश्लेषण कीजिए ।

“The issue of Parliamentary-privileges has been a bone of contention and conflict between the Parliament and the Judiciary.” Analyse this statement in the backdrop of decided cases.

10

- (e) “निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के एक अंतर्भूत अंग के रूप में संरक्षित है ।” इस कथन का न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (अवकाश प्राप्त) बनाम भारत संघ के निर्णय के आलोक में विशदीकरण कीजिए ।

“Right to Privacy is protected as an intrinsic part of life and personal liberty enshrined under Article 21 of the Constitution of India.” Elucidate this statement in the light of the decision of Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India.

10

- Q2.** (a) (i) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित प्रशासनिक अधिकरणों के विशेष उल्लेख के साथ भारत में अधिकरणों के विस्तार पर समीक्षा दीजिए ।
 (ii) “भारत में पंचायती राज प्रणाली को पुनरुज्जीवित करना न्यायपालिका पर कार्यभार को कम करने के सहायक के रूप में है ।” टिप्पणी कीजिए ।
 (i) Give an overview of the growth of the Tribunals in India with special reference to Administrative Tribunals established under the Administrative Tribunal Act.
 (ii) “Revival of the Panchayati Raj system in India is an aid to reduce the workload on the Judiciary.” Comment. 20
- (b) “संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति व्यापक तो है, परन्तु असीमित नहीं है ।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? विवेचना कीजिए कि क्या आधारीक संरचना के सिद्धान्त ने संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रबलित किया है अथवा नहीं ।
 “Power of the Parliament to amend the Constitution is wide, but not unlimited.” Do you agree with this statement ? Discuss whether the doctrine of basic structure has reinforced the power of judicial review under the Constitution. 15
- (c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों की प्रकृति का परीक्षण कीजिए और इसका अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों से विभेद कीजिए ।
 Examine the nature of the powers of the High Courts under Article 226 of the Constitution of India and distinguish it from the powers of the Supreme Court under Article 32. 15
- Q3.** (a) प्रशासन को प्रत्यायोजित विधान की शक्ति प्रदान करते हुए, सामर्थ्यकारी अधिनियम में अनुसरण किए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए । अधिनियम में अधिकथित अनिवार्यताओं के अनुपालन के क्या परिणाम होते हैं ? विनिश्चयित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए ।
 While conferring the power of delegated legislation on the administration, the enabling Act may specify the procedural safeguards to be followed in the exercise of the power. What are the consequences of non-compliance with the requirements as laid down in the Act ? Discuss with the help of decided cases. 20
- (b) “भारत का निर्वाचन आयोग भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्तशासी संवैधानिक प्राधिकरण है ।” भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों और प्रकार्यों की व्याख्या करते हुए टिप्पणी कीजिए ।
 “The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering the election process in India.” Comment by explaining the powers and functions of the Election Commission of India. 15

- (c) “इंडिया अर्थात् ‘भारत’, राज्यों का संघ होगा ।” व्याख्या कीजिए । क्या आपके विचार में भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है ? विनिश्चयित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए ।

“India that is ‘Bharat’, shall be a Union of States.” Explain. Do you think that the Indian Constitution is a Federal Constitution ? Discuss with the help of decided cases.

15

- Q4.** (a) ‘विधि-शासन’ से आपका क्या अभिप्राय है ? विधि-शासन के डायसी के सिद्धान्त का आधारिक तत्त्व यह है कि ‘आप कितने भी उच्च हों, विधि आपसे भी ऊपर है’ । विनिश्चयित वादों की सहायता से इसकी विवेचना कीजिए ।

What do you mean by the term ‘Rule of Law’ ? The basic element of Dicey’s doctrine of the rule of law is, ‘be you ever so high, the law is above you’. Discuss with the help of decided cases.

20

- (b) राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की विवेचना कीजिए । क्या अध्यादेश की विधिमान्यता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ? सुसंगत वाद-विधि को उद्धृत कीजिए ।

Discuss the Ordinance making power of the President. Can the validity of an Ordinance be challenged in the Court of Law ? Cite relevant case-law.

15

- (c) निम्नलिखित कथनों का परीक्षण और व्याख्या कीजिए :
- (i) लोक हित मुकदमेबाजी न्यायपालिका की राजनीति को बढ़ावा देने का एक साधन है ।
 - (ii) न्यायिक सक्रियता के न्यायपालिका पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं ।

Examine and explain the following statements :

15

- (i) Public Interest Litigation is a tool to promote politics of the Judiciary.
- (ii) Judicial Activism has both positive and negative impact on the Judiciary.

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) “अन्तर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लोपी बिन्दु है ।” व्याख्या कीजिए ।
 “International Law is the vanishing point of Jurisprudence.” Explain. 10
- (b) राज्य-मान्यता से आपका क्या अभिप्राय है ? मान्यता के विधिक प्रभाव क्या हैं ? तथ्यतः और विधितः मान्यता में विभेदन कीजिए ।
 What do you mean by State-Recognition ? What are the legal effects of recognition ? Differentiate between de-facto and de-jure recognition. 10
- (c) स्व-रक्षा के अपने अन्तर्निहित अधिकार के प्रयोग में, राज्यों के द्वारा विधिपूर्ण बलप्रयोग को नियन्त्रित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्या नियम हैं ?
 What are the rules of International Law governing the lawful use of force by the States in the exercise of their inherent right of self-defence ? 10
- (d) अन्तर्राष्ट्रीय लोकोपकारी विधि और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के मध्य क्या अन्तर है ?
 What is the difference between International Humanitarian Law and International Human Rights Law ? 10
- (e) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के विभिन्न तरीकों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए । क्या आप समझते हैं कि समाधान के यह तरीके (ढंग) प्रभावी हैं या कि वर्तमान परिदृश्य में अन्य कोई तरीके (ढंग) की आवश्यकता है ?
 Discuss in brief, the various modes of peaceful settlement of international disputes. Do you think that these modes of settlement are effective or is any other mode required in the present scenario ? 10

Q6. (a) अन्तर्राष्ट्रीय विधि और देशीय विधि के मध्य सम्बन्धों को विनिर्धारित करने वाली प्रचलित विभिन्न थ्योरियाँ क्या-क्या हैं ? भारत में राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि को किस प्रकार लागू किया जाता है ?

What are the various theories prevalent for deciding the relationship between International Law and Domestic Law ? How do the National Courts in India apply the International Law ?

20

(b) निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए :

- (i) निर्दोष मार्ग का सिद्धान्त
- (ii) अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उस पर अन्य राज्यों के अधिकार

Briefly explain the following :

15

- (i) Doctrine of Innocent Passage
- (ii) Exclusive Economic Zone and the rights of other States thereto

(c) “अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की प्रभाविता राज्यों द्वारा प्रदत्त सहयोग की मात्रा पर निर्भर करती है। यह सहयोग न केवल अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के राज्य-पक्षकार से संबद्ध होता है, बल्कि अपक्षकार राज्य से भी संबद्ध होता है।” विवेचना कीजिए।

“The effectiveness of the International Criminal Court depends on the degree of co-operation provided by the States. This co-operation concerns not only the State-party to the International Criminal Court but also the non-party State.” Discuss.

15

Q7. (a) राज्यों की प्रादेशिक अधिकारिता से आप क्या समझते हैं ? क्या आप इस अभिमत से सहमत हैं कि शरण माँगने का अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के अधीन पूर्णतः स्थापित है ? यदि ऐसा है, तो कारणों सहित अपने उत्तर की संपुष्टि कीजिए।

What do you understand by territorial jurisdiction of States ? Do you agree with the view that Right to Seek Asylum is firmly established under International Human Rights Law ? If so, substantiate your answer with reasons.

20

(b) परीक्षण कीजिए कि किस दूरी और सीमाओं तक एक संधि, एक तीसरे राज्य, जो संधि का पक्षकार नहीं है, को अधिकार प्रदान कर सकती है और दायित्व आरोपित कर सकती है।

Examine the extent and limits to which a treaty can confer rights and impose obligations on the third State which is not party to the treaty.

15

(c) “संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाने वाले मुद्दों, जिन्हें एक राष्ट्र द्वारा अकेले सुलझाया नहीं जा सकता है, को सुलझाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मंच के तौर पर नामित किया जाता है।” इस कथन के आलोक में महासभा के प्रकार्यों पर चर्चा कीजिए।

“United Nations is designated as the foremost forum to address the issues that transcend the national boundaries, which cannot be resolved by a country alone.” In the light of this statement, discuss the functions of the General Assembly.

15

Q8. (a) निम्नलिखित पर समालोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास
- (ii) राज्य प्रायोजित आतंकवाद

Write critical notes on the following :

20

- (i) International efforts towards protection and improvement of human environment
- (ii) State-sponsored terrorism

- (b) व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (सी.टी.बी.टी.) के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए । साथ ही उन कारणों की भी व्याख्या कीजिए कि भारत ने इस संधि को क्यों हस्ताक्षरित नहीं किया है ।

Discuss the main provisions of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT). Also explain the reasons why India has not signed this treaty.

15

- (c) प्रशुल्कों और व्यापार पर साधारण करार (गैट) के ऐतिहासिक उद्भव, उद्देश्यों और प्रमुख सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए ।

Explain the historical evolution, objectives and main principles of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

15

